

(तिथि 22 जून 2026, समय 18:10 (10 मिनट))

**मुख्य समाचार :-**

- हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक में गांवों में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाने सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
- राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं – किसानों ने पी एम किसान सम्मान निधि की तारीफ की।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गाँव धिराणा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने को मंजूरी दी।
- पंचकूला नगर निगम के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आई ए एस अधिकारी, आर के सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

\*\*\*\*\*

आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रीमंडल की बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती और शामलात भूमि देने का अधिकार जिला उपयुक्त को देने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि कुल 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिनमें से लगभग 13 पर निर्णय ले लिया गया है। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी दूर करने और गांवों में पटवारियों की उपलब्धता बढ़ाना शामिल है। इसके इलावा नए भर्ती 2600 पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि 18 माह से घटाकर 12 माह करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। सरकार का तर्क है कि लंबे प्रशिक्षण के कारण बड़ी संख्या में चयनित पटवारी गांवों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि कम होने से राजस्व रिकॉर्ड, इंतकाल, जमाबंदी और भूमि संबंधी सेवाओं के लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

\*\*\*\*\*

हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातत्व स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। यह प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु-सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु-सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी

\*\*\*\*\*

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व और क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जिनमें “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना”, “किसान क्रेडिट कार्ड योजना” और “किसान सम्मान निधि योजना” प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को बीज आदि की खरीद के लिए होने वाले खर्च से निपटने में राहत दी है और छोटे मोटे कृषि खर्चों के लिए कर्ज लेने से बचाया है। सबसे खास बात यह है कि यह राशि किसानों के बैंक खातों में बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी सिफारिश के सीधे पहुंच रही है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18 हजार 880 करोड़ से अधिक की राशि का सीधा हस्तांतरण किया गया। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के 15 लाख 95 हजार 644 लाभार्थी

किसानों के खातों में 319 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि पहुँची है। जींद के एक किसान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा हरियाणा के किसानों को अबतक कुल 23 किस्तों में 7 हजार 881 करोड़ 60 लाख रुपये मिले हैं।

\*\*\*\*\*

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के गांव धिराणा में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण और बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर लगभग 55 लाख 49 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस बजट से केंद्र में आवश्यक चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और मरीजों के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे धिराणा और आसपास के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा।

\*\*\*\*\*

पंचकूला नगर निगम के 79 करोड़ 46 लाख रुपये के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी आर.के. सिंह को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज तीन दिन का रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया। जिसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने इस दौरान रिमांड अवधि में हुई पूछताछ और जांच की प्रगति से अदालत को अवगत करवाया। गौरतलब है कि आर.के. सिंह पर पंचकूला नगर निगम से जुड़े कथित गबन मामले में भूमिका निभाने के आरोप हैं। सीबीआई इस मामले में वित्तीय लेन-देन, प्रशासनिक निर्णयों और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी की जांच कर रही है।

\*\*\*\*\*

हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नूह में खेल विभाग में तैनात उप अधीक्षक रामेहर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी कार जिला खेल विभाग, में ठेकेदार के माध्यम से मासिक किराये पर लगी थी किन्तु उसे इस वर्ष फरवरी से वाहन का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और खेल अधिकारी द्वारा उसके वाहन को पहली जून से विभागीय सेवा से भी हटा दिया गया। उसके बाद खेल विभाग के कुछ कर्मचारी उसकी गाड़ी को पुनः विभाग में लगाने के बदले एक लाख पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग रहे थे। ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

\*\*\*\*\*

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वदेशी उद्योगों में पिछले 12 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकल से ग्लोबल तक की परिकल्पना को ध्यान में रख कर बुनी गई खादी, आज देश की आर्थिक मजबूती और ग्रामीण समृद्धि का बड़ा आधार बन गई है। हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ बलप्रीत सिंह ने कहा कि सरकार ने इन 12 वर्षों खादी व ग्रामोद्योग पर विशेष ध्यान दिया है। लोगो को जहां अनुदान पर ऋण उपलब्ध हुआ वही डिजिटल मार्केटिंग द्वारा नया बाजार उपलब्ध हो रहा है।

\*\*\*\*\*

गन्नौर क्षेत्र के गांव खुबडू में आज सुबह सोनीपत अपराध शाखा और गन्नौर पुलिस की अपराध जांच एजेंसी की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर गोपाल मारा गया। मुठभेड़ के दौरान अपराध जांच एजेंसी के एक हवलदार देवेन्द्र के हाथ में भी गोली लगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गोपाल पर हत्या, हत्या की कोशिश, दुष्कर्म और अन्य गंभीर अपराधों सहित करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक गोपाल हत्या के दो मामलों में उम्रकैद की सजा भुगत

रहा गोपाल इसी वर्ष मार्च में मिली पैरोल खत्म होने पर 30 मई को वापस जेल जाने के बजाय भूमिगत हो गया था। इसके बाद उसने सोनीपत और पानीपत क्षेत्र में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया।

\*\*\*\*\*

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 4 व 5 जुलाई को ली जाने वाली एचटेट परीक्षा-2025 हेतु पंजीकरण करवाने वाले अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपने विवरणों में रह गई कोई भी त्रुटि ऑफलाइन माध्यम से दूर करवा सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने बताया की यह सुविधा 25 जून तक केवल कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक बोर्ड कार्यालय के कमरा नंबर-28 में मिलेगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की अपील की है।

\*\*\*\*\*